दैनिक
न्याय साक्षी
अधिकार से न्याय तक

आवश्यक सूचना

आप सभी को सूचित करते हर्ष हो रहा है, कि न्यायसाक्षी अधिकार से न्याय तक का सर्वे का कार्य तेजी से चल रहा है, जल्द ही सर्वे की टीम आपके घर विजिट करेगी, कृपया अपनी प्रति सुरक्षित कराएं।

RNI NO - CHHHIN/2018/76480 ‖ Postal Registration No-055/Raigarh DN CG ‖ रायगढ़, शनिवार 07 अगस्त 2021 ‖ पृष्ठ-4, मूल्य 3 रूपए ‖ वर्ष-03, अंक- 308

महत्वपूर्ण एवं खास

राष्ट्रीय विज्ञान शिक्षा और अनुसंधान संस्थान, भुवनेश्वर को ड्रोन के इस्तेमाल की मिली मंजूरी

नई दिल्ली (आरएनएस)। नागरिक उड्डयन मंत्रालय (एमओसीए)और नागरिक उड्डयन महानिदेशालय (डीजीसीए)नेराष्ट्रीय विज्ञान शिक्षा और अनुसंधान संस्थान (एनआईएसईआर)भुवनेश्वर को मानव रहित विमान प्रणाली (यूएएस) नियम, 2021 से सशर्त छूट दी है। इस छूटसेसंस्थान को ड्रोन काइस्तेमाल करके,भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण (एएसआई) के सहयोग से केंद्रद्वारासंरक्षित स्मारकों के हवाई सर्वेक्षण और फोटोग्रामेट्री की मंजूरी मिली है। राष्ट्रीय विज्ञान शिक्षा और अनुसंधान संस्थानकेलिएड्रोन संचालन हेतु मंजूर किए गए स्थलों में भुवनेश्वर स्थित राजा-रानी मंदिरऔर लिंगराज मंदिर शामिल हैं। यह छूट मंजूरीकी तारीख से एक वर्ष की अवधि के लिए या अगले आदेश तक, इनमें से जो भी पहले हो, के लिए वैध है और यह नागरिक उड्डयन महानिदेशालयद्वारा जारी मानक संचालन प्रक्रिया (एसओपी) केनियमों और शर्तों के अधीन होगी। इस महीने के शुरुआत में, हरियाणा के शहरी स्थानीय निकाय निदेशालय (डीयूएलबी) को भी अमृत (अटल नवीकरण और शहरी परिवर्तन मिशन) शहरों के विकास और हिसार, पंचकुलाएवं अंबाला शहरी क्षेत्रोंकीसंपत्ति कर सर्वेक्षण के उद्देश्य सेडेटा अधिग्रहण, मानचित्रण और वेब-आधारित जीआईएस (भौगोलिक सूचना प्रणाली)प्लेटफॉर्मके कार्यान्वयन के लिए ड्रोन के इस्तेमाल की मंजूरी दी गयी थी।

अफगानिस्तान में सेना के समर्थन में लोगों ने निकाली रैली

काबुल। अफगानिस्तान में लाखों लोगों ने राजधानी काबुल सहित देश भर में तालिबानी आतंकवादियों के खिलाफ लड़ रहे सुरक्षाबलों के समर्थन में 'अल्लाहु अकबर' नारा लगाते हुए रैली निकाली। रात हेरात शहर से रैली शुरू हुई। देश भर में इस तरह की कई रैली निकाले जाने की खबरें मिली हैं। रिपोर्ट के अनुसार कपिसा, बगलान, नूरिस्तान और सर-ए-पुल प्रांतों में लोग सशस्त्र बलों के लिए समर्थन में नारे लगाते हुए देखे गये। प्रांतीय गवर्नर अब्दुल सबूर कानी ने बताया कि सुरक्षाबलों ने बीती रात तालिबान द्वारा किए गए बड़े हमले को विफल करते हुए उन्हें पीछे धकेल दिया।

पाकिस्तान ने भारतीय राजदूत को किया तलब

इस्लामाबाद। पाकिस्तान ने जम्मू और कश्मीर की परिवर्तित स्थिति की दूसरी वर्षगांठ पर भारतीय राजदूत को विदेश मंत्रालय में तलब किया। पाकिस्तान विदेश मंत्रालय ने जम्मू और कश्मीर की विशेष स्थिति में परिवर्तन किए जाने की वर्षगांठ के अवसर पर अपनी 'स्पष्ट अस्वीकृति' से अवगत कराने के लिए भारतीय राजदूत सुरेश कुमार को तलब किया। इसके साथ ही पाकिस्तान ने इस्लामी सहयोग संगठन (ओआईसी) के स्वतंत्र स्थायी मानवाधिकार आयोग के एक दल को पाकिस्तान के कब्जे वाले कश्मीर में आमंत्रित किया और भारत के खिलाफ बयान जारी किए। पाकिस्तान की यह नापाक हरकत कश्मीर के विशेष दर्जा को समाप्त किए जाने की दूसरी वर्षगांठ के अवसर पर भारत के खिलाफ अंतरराष्ट्रीय समर्थन हासिल करने का प्रयास है।

अमेरिका में हुआ विमान हादसा, छह की मौत

वाशिंगटन। अमेरिका के अलास्का में एक विमान के दुर्घटनाग्रस्त होने की वजह से छह लोगों की मौत हो गई है। डी हैविलैंड बीवर विमान लगभग 19.20 बजे पर तटरक्षक बल को एक आपातकालीन संकेत भेजने के बाद केचिकन शहर के पास दुर्घटनाग्रस्त हो गया। घटना की जानकारी मिलने के बाद बचाव दल के दो तैराक मौके पर पहुंचे,लेकिन किसी को जीवित नहीं पाया। अभी तक हादसे की वजहों का पता नहीं चल पाया है।

डिजिटलीकरण का लाभ उठाने हेतु लचीले, मजबूत, सतत और समावेशी विकास के मॉडल को अपनाया गया

नई दिल्ली (आरएनएस)। इटली के ट्राइस्टे शहर में 5 अगस्त, 2020 को आयोजित जी20 डिजिटल मंत्रियों की बैठक में, जी20 मंत्रियों ने डिजिटलीकरण का लाभ उठाने के लिए लचीला, मजबूत, सतत और समावेशी विकास मॉडल अपनाने की घोषणा की। मंत्रियों ने डिजिटल अर्थव्यवस्था और डिजिटल सरकार के आधार पर सहयोग बढ़ाने की दिशा में काम करने पर सहमति व्यक्त की। इलेक्ट्रॉनिक्स और सूचना प्रौद्योगिकी मंत्री, अश्विनी वैष्णव ने वर्चुअल रूप से जुड़कर भारतीय प्रतिनिधिमंडल का नेतृत्व किया और डिजिटलीकरण में भारत की सफलता की कहानी साझा की। इलेक्ट्रॉनिक्स और सूचना प्रौद्योगिकी, राज्यमंत्री राजीव चंद्रशेखर भी बैठक में शामिल हुए।

वैष्णव ने डिजिटल समावेश और सामाजिक सशक्तिकरण के लिए 2015 से डिजिटल इंडिया के माध्यम से प्राप्त किए गए उपलब्धियों को साझा

किया। डिजिटल प्रौद्योगिकियों और सार्वजनिक डिजिटल प्लेटफॉर्म जैसे कि आधार, प्रत्यक्ष लाभ हस्तांतरण (डीबीटी) आदि के माध्यम से लोगों के सशक्तिकरण के बारे में बोलते हुए, उन्होंने कहा, 1.29 बिलियन लोगों को डिजिटल पहचान पत्र आधार प्रदान किया गया है। साथ ही 430 मिलियन गरीब लोगों के बैंक खाते खोले गए हैं। इन दोनों को जोड़ कर सीधे बैंक खातों में सरकार की जनकल्याणकारी योजना के लाभ भेज जा रहे हैं जिससे वितरण प्रणाली में गड़बड़ी समाप्त हो गया है। भारत के लगभग 900 मिलियन नागरिक एक या अधिक योजनाओं का लाभ प्राप्त कर रहे हैं। इसने न केवल आम नागरिकों को सशक्त बनाया है बल्कि पिछले सात वर्षों में 24 अरब अमेरिकी डॉलर से अधिक की बचत भी की है।

वैष्णव ने महामारी के दौरान डिजिटल समावेशन के महत्व पर भी प्रकाश डाला, जिसके लिए भारत एक मजबूत समर्थक रहा है। उन्होंने कहा कि प्रौद्योगिकी डिजिटल समावेशन के लिए है न कि डिजिटल विभाजन पैदा करने के लिए और भारत हमेशा इस बात की वकालत करता रहा है कि डिजिटल अर्थव्यवस्था सामाजिक समावेश के लिए एक महत्वपूर्ण माध्यम है। उन्होंने जी20 फोरम में घनिष्ठ भागीदारी के लिए भारत के समर्थन की प्रतिबद्धता जताई और देशों को डिजिटल समावेशन और सामाजिक सशक्तिकरण की दिशा में भविष्य में सहयोग के लिए आमंत्रित किया।

राज्यमंत्री राजीव चंद्रशेखर ने डिजिटल इंडिया कार्यक्रम के तहत डिजिटल प्लेटफॉर्म और कनेक्टिविटी सहित मजबूत और सुरक्षित डिजिटल बुनियादी ढांचे की उपलब्धता के लिए भारत के मॉडल को जी20 देशों के साथ साझा किया। चंद्रशेखर ने 'आधार' (विशिष्ट डिजिटल पहचान) की भूमिका के बारे में बताया कि कैसे यह भारत के निवासियों को कभी भी, कहीं भी प्रमाणितत करने के लिए सशक्त माध्यम बन गया है और एक कुशल और पारदर्शी तरीके से सरकारी सब्सिडी का लाभ और सेवाओं का सफलतापूर्वक वितरण प्रदान करता है।

उन्होंने इस बात पर जोर दिया कि दुनिया के इतिहास में किसी भी समय से अधिक, प्रौद्योगिकी और डिजिटलीकरण का इस्तेमाल कोविड-19 के दौरान सरकारों द्वारा किया गया है। कोविड की वजह से जीवन, आजीविका और अर्थव्यवस्थाएं बाधित हुई हैं।

केंद्र के हिस्से के रूप में राज्यों को 23,145 करोड़ दिये गए : सरकार

» स्मार्ट सिटी योजना

नई दिल्ली (आरएनएस)। सरकार ने संसद की एक समिति को बताया कि स्मार्ट सिटी मिशन के तहत केंद्र के हिस्से के रूप में राज्यों/संघ राज्य क्षेत्रों को अब तक 23,145 करोड़ रूपये की राशि हस्तांतरित की जा चुकी है। वर्ष 2021-22 के लिये अनुदान की मांग पर शहरी विकास संबंधी स्थायी समिति के पांचवें प्रतिवेदन में अंतर्विष्ट सिफारिशों पर सरकार द्वारा की गई कार्रवाई संबंधी रिपोर्ट में यह बात कही गई है। यह रिपोर्ट शुक्रवार को लोकसभा में पेश की गई।

रिपोर्ट के अनुसार, स्मार्ट शहरों के लिये बजट के संबंध में समिति की सिफारिशों को लेकर सरकार ने अपने उत्तर में कहा कि स्मार्ट सिटी मिशन के तहत केंद्र के हिस्से के रूप में राज्यों/संघ राज्य क्षेत्रों को अब तक 23,145 करोड़ रूपये की राशि हस्तांतरित की जा चुकी है। यह केंद्र सरकार द्वारा प्रस्तावित 100 स्मार्ट शहरों के लिये 48 हजार करोड़ रूपये की कुल वित्तीय सहायता का करीब 48 प्रतिशत है। इसमें कहा गया है कि भारत सरकार के हिस्से में स्मार्ट सिटी द्वारा सूचित खर्च 20,167 करोड़ रूपये है। रिपोर्ट के अनुसार, पिछले तीन वर्षों में धन का उपयोग मार्च 2018 में 1,032 करोड़ रूपये से बढ़कर वर्ष 2021 में 20,167 करोड़ रूपये हो गया।

देश में बढ़ा कोरोना महामारी का प्रकोप

» 24 घंटों में सामने आए 44,643 नए मामले, 464 की मौत

नई दिल्ली (आरएनएस)। देश में कोरोना के मामलों ने फिर रफ्तार पकड़ ली है। अचानक से नए मामलों में तेजी देखी जा रही है। लगातार चौथे दिन देश में नए केसों की संख्या 40 हजार से अधिक दर्ज की गई है। बीते 24 घंटे में 44 हजार से ज्यादा केस सामने आए हैं, जबकि 464 लोगों की मौत हुई है।

केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्रालय के आंकड़ो के अनुसार 24 घंटे में देश में 44,643 नए मामले दर्ज किये गये। जबकि 41096 मरीज स्वस्थ होकर घर लौट गए हैं। देश में अब भी सक्रीय मरीजों की संख्या 4,14,159 है। हालांकि रोजाना सामने आने वाले केस में आधे से अधिक सिर्फ दो राज्यों- केरल और महाराष्ट्र से हैं। स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्रालय द्वारा जारी आंकड़ों के मुताबिक बीते 24 घंटे में 44,643 नए मामलों की पुष्टि हुई है। आपको बता दें कि इनमें से करीब 22 हजार केरल में सामने आए हैं।

कोरोना से ठीक होने वालों की बात करें तो बीते 24 घंटे में 41,096 मरीजों ने कोरोना महामारी को मात दी है। देश में रिकवरी रेट 97.36 प्रतिशत के करीब है। अभी तक भारत में कुल 3,10,15,844 मरीज या तो स्वस्थ हो चुके हैं या फिर उन्हें अस्पताल से छुट्टी दी जा चुकी है। हालांकि, एक्टिव केस जरूर राज्य सरकारों के साथ-साथ केंद्र की चिंता बढ़ाने वाली है। फिलहाल देश में 4,14,159 एक्टिव केस हैं, जो कि करीब 1.30 प्रतिशत है।

पाकिस्तान के साथ सिंधु जल संधि पर पुनः विचार विमर्श करे भारत

» संसदीय समिति ने सरकार को अपनी रिपोर्ट में दिया सुझाव

नई दिल्ली (आरएनएस)। संसद की एक समिति ने वर्तमान सिंधु जल संधि में जलवायु परिवर्तन, वैश्विक तापमान, पर्यावरणीय प्रभाव जैसे विषयों के शामिल नहीं होने का जिक्र करते हुए कहा कि भारत सरकार को पाकिस्तान के साथ इस जल संधि पर पुनः विचार विमर्श करना चाहिए। लोकसभा में पेश डा. संजय जायसवाल की अध्यक्षता वाली, जल संसाधन संबंधी संसद की स्थायी समिति की रिपोर्ट में यह बात कही गई है। रिपोर्ट के अनुसार समिति यह पाती है कि यद्यपि सिंधु जल संधि समय की कसौटी पर खरी उतरी है, फिर भी उसका विचार है कि संधि को वर्ष 1960 में समझौते के समय मौजूद जानकारी और प्रौद्योगिकी के अनुसार बनाया गया था। इसमें कहा गया है कि उस समय दोनों देशों का दृष्टिकोण बांधों, नहरों के निर्माण, विद्युत ऊर्जा के उत्पादन के माध्यम से नदी प्रबंधन तथा पानी के उपयोग तक ही समिति था। समिति ने कहा कि वर्तमान समय में जलवायु परिवर्तन, वैश्विक तापमान, पर्यावरणीय प्रभाव का मूल्यांकन आदि अहम विषय हैं जिन्हें उस समय संधि में शामिल नहीं किया गया था, इसलिये संधि पर पुनः विचार विमर्श करने की आवश्यकता है।

रिपोर्ट में कहा गया है कि इसको ध्यान में रखते हुए समिति इस जल संधि पर भारत सरकार सेपाकिस्तान के साथ पुनः विचार विमर्श करने के लिये कूटनीतिक उपाय करने का आग्रह करती है। समिति ने यह भी कहा कि यद्यपि भारत को सिंधु जल संधि के अनुसार पश्चिम नदियों पर 36 लाख एकड़ फीट (एमएएफ) तक पानी का भंडारण करने का अधिकार है लेकिन भारत द्वारा अब तक कोई भंडारण क्षमता नहीं बनाई गई है। इसमें कहा गया है कि पश्चिम नदी विद्युत परियोजनाओं से लगभग 20 हजार मेगावाट की अनुमानित विद्युत क्षमता को हासिल किया जा सकता है लेकिन अभी तक केवल 3482 मेगावाट क्षमता का ही निर्माण किा जा सका है। रिपोर्ट में कहा गया है कि संधि भारत के लिये यह उपबंध करती है कि वह पश्चिमी नदियों के पानी से 13,43,477 एकड़ सिंचित फसल क्षेत्र को विकसित कर सकता है।

अमृत महोत्सव पर आरएसईटीआई संस्थानों ने 87 मोबिलाइजेशन कैंप आयोजित किए

नई दिल्ली (आरएनएस)। अमृत महोत्सव समारोह के हिस्से के रूप में, ग्रामीण स्वरोजगार प्रशिक्षण संस्थानों (आरएसईटीआई) ने 30 जुलाई और 5 अगस्त, 2021 के बीच देश भर में लगभग 87 मोबिलाइजेशन कैंप का आयोजन किया। 'आजादी का अमृत महोत्सव' देश की आजादी की 75वीं वर्षगांठ के उपलक्ष्य में भारत सरकार द्वारा आयोजित किए जा रहे कार्यक्रमों की एक श्रृंखला है। यह महोत्सव जन-भागीदारी की भावना के साथ पूरे देश में एक जन-उत्सव के रूप में मनाया जाएगा।

देश के 19 राज्यों और दो केंद्र शासित क्षेत्रों के 87 जिलों में कुल 87 मोबिलाइजेशन कैंप आयोजित किए गए। इस अभियान के दौरान, प्रतिभागियों को न केवल विभिन्न प्रकार के पाठ्यक्रमों के बारे में जागरूक किया गया, बल्कि बड़ी

संख्या में आकर्षित करने के लिए वृक्षारोपण अभियान, मास्क और राशन वितरण आदि जैसी गतिविधियोंका भी आयोजन किया गया था।

आरएसईटीआई के तहत कुल 37.81 लाख उम्मीदवारों को 64 पाठ्यक्रमों (59 राष्ट्रीय कौशल योग्यता संरचना (एनएसक्यूएफ) संबद्ध और पांच ग्रामीण विकास मंत्रालय द्वारा स्वीकृत) में प्रशिक्षित किया गया है और 26.65 लाख उम्मीदवारों को स्वरोजगार मिला है। यह कार्यक्रम इस समय देश के 18 राज्यों और सात केंद्र शासित क्षत्रों में लागू किया जा रहा है और 23 शीर्ष बैंकों (सार्वजनिक और निजी क्षेत्र के साथ-साथ कुछ ग्रामीण बैंकों) ने 585 चालू आरएसईटीआई को प्रायोजित किया है।

ग्रामीण स्वरोजगार प्रशिक्षण संस्थान (आरएसईटीआई) कार्यक्रम ग्रामीण विकास मंत्रालय, राज्य सरकारों और प्रायोजक बैंकों के बीच एक त्रिपक्षीय साझेदारी है। ग्रामीण युवाओं को स्वरोजगार/उद्यमिता उद्यम शुरू करने की खातिर शिक्षण प्रदान करने के उद्देश्य से बैंकों के लिए अपने शीर्ष जिले में कम से कम एक आरएसईटीआई खोलना अनिवार्य है। आरएसईटीआई कार्यक्रम उद्यमियों के अल्पकालीन प्रशिक्षण और दीर्घकालीन मार्गदर्शन के दृष्टिकोण के साथ चलता है। 18-45 वर्ष के आयु वर्ग के ग्रामीण गरीब युवा प्रशिक्षण में शामिल होने की पात्रता रखते हैं। ग्रामीण गरीब युवाओं की आकांक्षाओं को पूरा करने और उन्हें क्षेत्र और उद्यमिता कौशल में प्रशिक्षण देकर लाभदायक उद्यमियों में बदलने में आरएसईटीआई अग्रणी भूमिका निभा रहे हैं।

मोबिलाइजेशन कैंप कार्यक्रम का एक अभिन्न अंग हैं क्योंकि उनसे संभावित उम्मीदवारों तक पहुंचने और उन्हें योजना एवं इसके प्रावधानों के बारे में सूचित करने के पर्याप्त अवसर मिलते हैं। इस तरह के अभियानमें शामिल अन्य गतिविधियों के बीच, उपस्थित लोगों के लिए कई तरह के वित्तीय खेलभी आयोजित किए जाते हैं।

कोविशील्ड, कोवैक्सीन टीकों की मासिक उत्पादन क्षमता बढ़ाने की योजना : सरकार

नई दिल्ली (आरएनएस)। सरकार ने लोकसभा को सूचित किया कि कोविशील्ड टीके की मासिक उत्पादन क्षमता 11 करोड़ खुराक से बढ़ाकर 12 करोड़ से अधिक करने और कोवैक्सीन की क्षमता हर महीने ढाई करोड़ खुराक से बढ़ाकर करीब 5.8 करोड़ करने की योजना है।

स्वास्थ्य राज्य मंत्री भारती पवार ने लोकसभा को एक प्रश्न के लिखित उत्तर में बताया कि राष्ट्रीय कोविड-19 टीकाकरण कार्यक्रम के लिए सीरम इंस्टीट्यूट ऑफ इंडिया ने 16 जनवरी से पांच अगस्त तक कोविशील्ड की 44.42 करोड़ खुराकों की आपूर्ति की, वहीं भारत बायोटेक ने कोवैक्सीन की 6.82 करोड़ खुराकों की आपूर्ति की। देश में टीकों के विनिर्माण या उत्पादन की क्षमता से संबंधित प्रश्न के उत्तर में उन्होंने कहा, ''जैसा कि निर्माताओं ने बताया है कि कोविशील्ड की मासिक उत्पादन क्षमता 11 करोड़ खुराक प्रति माह से बढ़ाकर 12 करोड़ से अधिक प्रति माह करने की वहीं कोवैक्सीन की उत्पादन क्षमता ढाई करोड़ खुराक प्रति माह से बढ़ाकर करीब 5.8 करोड़ खुराक प्रति माह करने की योजना है। उन्होंने कहा कि केंद्रीय औषधि मानक नियंत्रण संगठन ने टीकों को तेजी से मंजूरी देने के लिए अनेक कदम उठाये हैं।

केंद्रीय कर्मियों को डीए के बाद अब एरियर मिलने की उम्मीद

» सरकार के साथ नीति बनाने को तैयार हैं कर्मचारी

नई दिल्ली (आरएनएस)। केंद्र सरकार के 48 लाख कर्मचारी और 65 लाख पेंशनर्स को महंगाई भत्ता व महंगाई राहत दी जा चुकी है। अब सरकारी कर्मियों ने बीते 18 माह का एरियर लेने के लिए कदम आगे बढ़ाया है। केंद्र सरकार ने भत्ते की दर 17 फीसदी से बढ़ाकर 28 फीसदी कर दी थी।

कर्मियों का कहना है कि सरकार ने 18 माह के एरियर को लेकर कोई घोषणा नहीं की। एरियर न मिलने से

कर्मियों को भारी आर्थिक नुकसान झेलना पड़ा है। स्टाफ साइड की राष्ट्रीय परिषद के सचिव शिव गोपाल मिश्रा ने इस बाबत कैबिनेट सचिव को पत्र लिख दिया है। इसमें उन्होंने कहा है कि भले ही सरकार एक साथ एरियर न दे। उसे किस तरह जारी किया जाए, इस संबंध में कर्मचारी संगठन और सरकारी प्रतिनिधि बैठक कर पॉलिसी का निर्धारण कर सकते हैं। केंद्र सरकार ने 18 माह तक बंद रहे डीए की राशि को 17 फीसदी से बढ़ाकर 28 फीसदी कर दिया था। इसे एक जुलाई से जारी किया गया है। इस डीए राशि का एरियर देने बाबत सरकार ने कोई घोषणा नहीं की। नेशनल काउंसिल ऑफ जेसीएम के सचिव (स्टाफ साइड) शिव गोपाल मिश्रा ने इस संबंध में पिछले माह कैबिनेट सचिव राजीव गौबा को पत्र लिखा है। इसमें उन्होंने कहा है कि कर्मियों का एरियर नहीं रोका जाना चाहिए, यह उन्हीं की सेलरी का हिस्सा है। उन्होंने कोरोना महामारी के खतरनाक दौर में सरकार के साथ कदम से कदम मिलाकर काम किया है। सरकार को 18 माह के एरियर की घोषणा बिना किसी देरी के कर देनी चाहिए। मिश्रा ने कैबिनेट सचिव से आग्रह किया है कि अगर सरकार चाहे तो इसे तीन किश्तों में जारी कर सकती है। ये किश्त कब और कितने माह के अंतराल पर दी जाएंगी, इस पर कर्मचारी संगठन, सरकार के साथ बातचीत करने के लिए तैयार हैं।

केंद्र सरकार द्वारा एरियर दिया जाता है तो उसका सीधा फायदा मौजूदा 48 लाख कर्मचारियों व 65 लाख पेंशनभोगियों को पहुंचेगा। सरकार ने जब डीए देने की घोषणा की थी तो इस बात का उल्लेख किया था कि एक जनवरी, 2020 से 30 जून, 2021 तक डीए व डीआर की दर 17 फीसदी ही मानी जाएगी। केंद्रीय मंत्री अनुराग ठाकुर ने कहा था, अब 28 फीसदी के हिसाब से महंगाई भत्ता मिलेगा। उस वक्त उन्होंने एरियर को लेकर कोई बात नहीं कही। केंद्रीय मंत्री की घोषणा का अर्थ यह था कि बढ़े हुए डीए की दर एक जुलाई 2021 से 28 फीसदी मान ली जाए। इसके अनुसार जून 2021 और जुलाई 2021 के बीच डीए में एकाएक 11 फीसदी वृद्धि हो गई, जबकि डेढ़ साल की अवधि में डीए की दरों में कोई वृद्धि दर्ज नहीं की गई। कर्मचारी एसोसिएशन के पदाधिकारी बताते हैं कि इस बाबत जेसीएम की आगामी बैठक में एरियर को लेकर अहम बातचीत होगी। स्टाफ साइड की तरफ से केंद्र सरकार को बता दिया गया है कि उसे कर्मियों के एरियर का भुगतान करना होगा।